

लवि : अब नए प्रारूप पर देना होगा पीएचडी सीटों का ब्योरा

लखनऊ : लखनऊ विश्वविद्यालय ने शैक्षिक सत्र 2021-22 की पूर्णकालिक पीएचडी दाखिले की प्रक्रिया शुरू करने से पहले कालेजों को सेंट व शिखरों का विवरण भेजने का एक और मौका दिया है। इस बार सूचना देने के प्रारूप में बदलाव कर कुछ नई चीजें शामिल की गई हैं। ब्योलेंजों को इसमें सूचना भेजकर 11 जून तक विश्वविद्यालय को विभागीय शोध समिति (डीआरसी) में शामिल करने के लिए उपलब्ध करना होगा। इस संबंध में कुलसचिव डा. विनोद कुमार सिंह ने सभी राजकीय व अनुदानित कालेजों को निर्देश जारी कर दिए हैं। पीएचडी सीटों के लिए बोलें 30 अप्रैल को विभागों और कालेजों को पत्र भेजा था। सत्र मई तक कालेजों को अपने वहां पीएचडी के खाली सीटों, शिक्षकों के संबंध में सूचना विश्वविद्यालय के विभागध्यक्षों को भेजनी थी। वहीं, विभागों को विभागीय शोध समिति (डीआरसी) के माध्यम से सीटों को विषयवार सूची कुलसचिव और प्रवेश समन्वयक को 15 मई तक उपलब्ध करानी थी। इस दौरान कुछ कालेजों ने अधूरी सूचनाएं भेज दीं। ऐसे में अब कालेजों को फिर से नया प्रारूप भेजना है।

बे देनी होगी सूचना : नए निर्देश के मुताबिक प्रत्येक राजकीय व अनुदानित महाविद्यालय को विभागवार विवरण के प्रारूप के अनुसार सूचना देनी है। इसमें शिक्षक नाम, पदनाम, निवृत्तता की तिथि, सीटों की संख्या, शोधरत शोधार्थियों की संख्या, विज्ञापित की जाने वाली सीटों की संख्या, शिक्षक का मोबाइल नंबर व ई-मेल बताना होगा। इसमें प्रत्येक विषय के लिए अलग विवरण देना होगा। इसके अलावा नए सुपरवाइजर का पूरा विवरण के निर्देश दिए गए हैं।

पी-पीएचडी कोर्स वर्क के परिणाम

31 तक जमा करें शुल्क

लखनऊ विश्वविद्यालय ने एलएलबी, इंजीनियरिंग तथा आइएमएस पाठ्यक्रमों में पूर्णकालिक विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति वीथी, छुट्टी, आठ व दस के सेमेस्टर के विद्यार्थियों को बिना विलंब शुल्क सेमेस्टर फीस 31 मई तक जमा करने का मौका दिया है। कुलसचिव डा. विनोद कुमार सिंह ने निर्देश जारी कर दिए। विद्यार्थियों को अपनी कक्षा के अनुसार अनलाइन अनुमति लेकर यूडीआरसी पोर्टल पर यह शुल्क जमा करना होगा। इसके लिए स्नातक पाठ्यक्रम के विद्यार्थियों को संशोधन संकाय के अविद्यार्थी कार्यालय, परास्नातक पाठ्यक्रम वाले को विभागाध्यक्ष कार्यालय और संस्थानों में संघालिता पाठ्यक्रम के विद्यार्थियों को संबंधित संस्थान के निदेशक कार्यालय से संपर्क कर अनलाइन अनुमति लेनी होगी।

जारी : लखनऊ विश्वविद्यालय के विधि संकाय की ओर से प्रो-पीएचडी कोर्स वर्क-2020-21 के परिणाम जारी कर दिए गए हैं। शोधार्थी अपने परिणाम विश्वविद्यालय को वेबसाइट www.lkouniv.ac.in पर देख सकते हैं। 16 विद्यार्थी सफल घोषित किए गए हैं।

एकदली लेब का उद्घाटन आज: लखनऊ विश्वविद्यालय में वंग के विद्यार्थी मानव शरीर को संरचना के बारे में भी जान सकते हैं। इसके लिए जानकोपुरम के नवीन परिसर स्थित वंग संकाय में एनाटॉमी लेब स्थापित की गई है। शुक्रवार को संकाय के स्थापना दिवस पर इसका उद्घाटन कुलपति प्रो. अलोक कुमार राय करेंगे। वंग संकाय के कोऑर्डिनेटर डा. अमरजित राय ने बताया कि मानव शरीर रचना विज्ञान प्रयोगशाला (एनाटॉमी लेब) विद्यार्थियों के लिए जल्दी लाभदायक होगी।

एलयू : पीएचडी के लिए नया प्रारूप जारी

लखनऊ। लखनऊ विश्वविद्यालय ने शैक्षिक सत्र 2021-22 में पीएचडी दाखिले के लिए दोबारा कॉलेजों से आवेदन मांगे हैं। इसके लिए नया प्रारूप भी जारी किया है। इसके अनुसार कॉलेजों को 11 जून तक इसके लिए योग्य शिक्षकों की जानकारी उपलब्ध करानी होगी। इसके बाद विवि प्रशासन सीटों का निर्धारण करेगा। रजिस्ट्रार ने संबद्ध कॉलेजों को भेजे पत्र में कहा है कि 30 अप्रैल को पीएचडी दाखिले से संबंधित सूचना कॉलेजों से मांगी गई थी, लेकिन कई कॉलेजों ने आधी-अधूरी सूचना भेजी है। ऐसे में एक प्रोफार्मा जारी किया जा रहा है, जिसमें प्रत्येक राजकीय व अनुदानित

कॉलेजों को इसी के अनुसार 11 जून तक करना होगा आवेदन

महाविद्यालय को शिक्षक का नाम, पदनाम, निर्धारित सीटों की संख्या, पहले से शोधार्थियों की संख्या, विज्ञापित की जाने वाली सीटों की संख्या आदि का विवरण देना होगा। इसमें हर शिक्षक के बारे में अलग विवरण व सुपरवाइजर का भी विवरण देना होगा। विवि ने इसके लिए नया पीएचडी अध्यादेश पास किया गया है। इसके अनुसार प्रवेश आवेदन शुरू करने से पहले संबंधित शिक्षकों व उनकी सीटों का निर्धारण किया जाना है, जिसके लिए कॉलेजों से सूचना मांगी गई है जो विवि की डीआरसी से एप्रूव होकर प्रवेश कार्यालय भेजी जाएगी। इसके बाद प्रवेश आवेदन प्रक्रिया शुरू होगी। (माई सिटी रिपोर्टर)

FIRST INDIA PAGE 13

Gender Sensitisation

CITY FIRST

Under the National Education Policy (NEP) 2020, the Institute of Women's Studies, Lucknow University has come up with three new papers on gender studies. At the board of Studies meeting held on Wednesday, these three co-curricular courses were proposed to be started at the undergraduate level in LU. Giving an impetus to Mission Shakti, these vocational courses will add practical value, enhancing students' skillset thereby opening more avenues for their employability.

As a co-curricular course dealing with issues and topics on Gender, Violence and Mental Health, these papers will

be a part of the syllabus in the third semester at LU. In addition to this, two vocational courses will be added in the fourth semester of graduation. This includes Women and Entrepreneurship Skill Development and Women, Leadership and Management. To introduce the idea of entrepreneurship and its processes and add avenues for women entrepreneurs, the courses will add practical value to all students, irrespective of their gender. These papers



will help students by widening the scope of specialisation in gender-based violence studies and counselling. The vocational course will amp up the employability skills of students by developing their understanding of leadership and management.



प्रो. मनोज अग्रवाल, अध्यक्ष, लखनऊ विश्वविद्यालय में देश का अग्रणी राज्य बन चुका है। इससे कृषि तथा उद्योगों का तीव्र विकास संभव हो सकेगा। उत्तर प्रदेश सरकार के 2022-23 के बजट में कुशलता, उत्पादकता पर विशेष ध्यान दिया गया है। प्रदेश में बढ़ती हुई ऊर्जा की जरूरतों को देखते हुए कम कीमत पर सोलर एनर्जी पर विशेष ध्यान दिया गया है। वह चाहे सोलर पम्प के रूप में हो, बुनकरों को सोलर इन्वर्टर के रूप में हो। कुल मिलाकर योगी सरकार का छठवां बजट उत्तर प्रदेश को बीमारू राज्य श्रेणी से निकालकर जुझारू राज्य एवं प्रगतिवादी राज्य की श्रेणी में लाकर खड़ा कर दिया है।

PIONEER PAGE 3

एलयू: 31 मई तक सेमेस्टर शुल्क जमा करें

लखनऊ। लखनऊ विश्वविद्यालय ने 31 मई तक सेमेस्टर शुल्क बिना विलम्ब शुल्क जमा करने का मौका दिया है। सत्र 2021-22 एलएलबी, इंजीनियरिंग और आईएमएस पाठ्यक्रमों को छोड़कर सेमेस्टर चार, छह, आठ व दस के विद्यार्थियों को अपने विभाग के अधिकारी से अनुमति प्राप्त कर 31 मई तक यूडीआरसी पोर्टल पर शुल्क जमा करने के निर्देश दिए गए हैं।

11 जून तक शिक्षकों की जानकारी दें डिग्री कॉलेज

लखनऊ। लखनऊ विश्वविद्यालय के सभी सम्बद्ध महाविद्यालयों को 11 जून तक विभागवार अर्ह शिक्षकों का विवरण देना होगा। एलयू कुलसचिव ने सभी प्राचार्यों को इस सम्बंध में पत्र जारी कर दिया है। संशोधित पीएचडी अध्यादेश के अनुसार अर्ह शिक्षकों के लिए विश्वविद्यालय ने विवरण प्रारूप जारी किया है।

अब सेमेस्टर फीस 31 तक जमा करें

लखनऊ यूनिवर्सिटी प्रशासन ने एलएलबी, इंजीनियरिंग व इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज के कोर्सज के रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स को छोड़कर, चौथे, छठे, आठवें व दसवें सेमेस्टर के स्टूडेंट्स को बिना लेट फीस के साथ 31 मई तक सेमेस्टर फीस जमा करने का मौका दिया है। गुरुवार को रजिस्ट्रार डॉ. विनोद सिंह ने इस संबंध में निर्देश जारी कर दिया। स्टूडेंट्स को अपनी क्लास के अनुसार ऑनलाइन अनुमति लेकर यूडीआरसी पोर्टल पर यह फीस जमा करनी होगी।

ट्रिलियन डॉलर के ट्रैक पर बजट

LUCKNOW (26 May): योगी 2.0 का पहला बजट जहां एक ओर अपने पुराने प्रयासों को सुदृढ़ करते हुए आगे बढ़ने की रणनीति बनाता है। वहीं वह एक ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था की आकांक्षा के अनुरूप नए ताने बाने को भी बनाता हुआ नजर आता है। 2022-23 का उत्तर प्रदेश का यह बजट समावेशी प्रगतिगामी तथा पोषणीय होने के साथ-साथ विकास के नए आयाम सृजित करता हुआ नजर आता है। यह बजट उत्पादन वृद्धि पर विशेष ध्यान देता हुआ प्रतीत होता है क्योंकि कृषि विकास पर 5 प्रतिशत से ज्यादा रखने का लक्ष्य है। वहीं ओडीओपी तथा सेवा क्षेत्र जैसे की पर्यटन, यातायात, आईटी क्षेत्र आदि पर भी जोर दिया गया है। जिसमें पहले के बजटों में किए गए प्रयासों की सफलता का प्रमाण भी मिलता नजर आ रहा है। इस प्रक्रिया को और मजबूत करने के लिए नए निवेश तथा



पूरा रणनीतियों पर ध्यान केंद्रित किया गया है। जैसे कि निजी निवेश को प्रोत्साहित करना आधारभूत संरचना के विकास एवं उनकी उत्पादकता बढ़ाने के लिए औद्योगिक लॉजिस्टिक्स जैसी गतिविधियों को प्रोत्साहित करना ताकि कृषि तथा औद्योगिक क्षेत्र के बीच बढ़ती आवश्यकताओं की पूर्ति पर भी जोर दिया गया है। जिसमें विकास की गति को तेज किया जा सके। विकास की बढ़ती संभावनाओं के बीच बढ़ती आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए ऊर्जा क्षेत्र में सुधार के साथ-साथ कम लागत पर सौर ऊर्जा उपलब्ध कराने पर विशेष ध्यान केंद्रित किया गया है। वह चाहे सोलर पंप, बुनकरों

के लाइट, ग्रामीण सड़कों पर प्रकाश के लिए या बुंदेलखंड में ग्रीन एनर्जी कारिडोर के रूप में हो। इसी प्रकार ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ बनाने, महिला सशक्तिकरण को प्रोत्साहित करना, शहरी अर्थव्यवस्था को पोषणीय बनाना इसी ऋंखला की एक कड़ी है। यह बजट शिक्षा के क्षेत्र में निजी निवेश के साथ-साथ उसके आधुनिकीकरण पर भी जोर देता है। बजट रणनीति की विशेषता यह है कि यह अंतरिक्षीय विषयताओं को कम करता हुआ नजर आता है। कुल मिलाकर योगी सरकार यह बजट ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्था के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए पुराने स्रोतों को सुदृढ़ करने के साथ-साथ विकास के नए स्रोतों सृजित करता प्रतीत होता है। जिसमें महिलाओं और छात्राओं की विशेष भूमिका नजर आती है। **प्रो. एमके अग्रवाल** एचओडी, अर्थशास्त्र विभाग, लखनऊ यूनिवर्सिटी